

बिहार सरकार
अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एव विकास विभाग)

का०आ०स०-स्था०1/आ०2-24/15

328

पटना, दिनांक 26.09.18

कार्यालय आदेश

श्रीमती अलका सिन्हा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मनेर प्रखंड, पटना सम्प्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, गुप्तवार्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय (मुख्यालय) सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के विरुद्ध राजस्व एव भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-760 दिनांक-25.06.2015 के साथ सलग्न जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-849 दिनांक-25.03.2015 के आलोक में निदेशालय के का०आ०स०-250 सहपठित ज्ञापक-1648 दिनांक-07.10.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2 अपर समाहर्ता, (विभागीय जॉच), पटना-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना द्वारा पत्रांक-95 दिनांक-29.06.2017 के माध्यम से श्रीमती अलका सिन्हा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नांकित है:-

कंडिका-1 सलग्न तथ्यो एवं साक्ष्यो, आरोपी के कारणपृच्छा एवं इसके समर्थन में दाखिल राक्ष्य आदि का परीक्षण एव परिशीलन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा दिए गए निदेश के बावजूद भी आरोपी द्वारा नगर पंचायत, मनेर के सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। यह स्पष्ट रूप से वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना/अनुशासनहीनता एव स्वेच्छाचारिता है। यदि बैठक बुलाने में कोई वैधानिक समस्या थी, तो उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, पटना से स्वयं मिलकर या पत्र द्वारा अपनी बात रखनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

आरोपी पर इस कंडिका में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

कंडिका-2 आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि सलग्न तथ्यो एव साक्ष्यो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा सूफी महोत्सव के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया गया, जिस कारण महोत्सव को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने में जिला प्रशासन को काफी कठिनाई हुई, फलस्वरूप जिलापदाधिकारी, पटना को उनके विरुद्ध प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदित करना पड़ा।

आरोपी पर इस कंडिका में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

कंडिका-3 आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता के आदेश एव उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद भी कमरा आवंटित नहीं किया जा रहा था, उन्हें इस मामले को शान्ति-पूर्ण ढंग से वार्ता कर सुलझा लेना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा बिना आपसी समन्वय स्थापित किए कार्य किया गया, जिससे कार्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जो अनुशासनहीनता एव स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

इस प्रकार आरोप पत्र में गठित सभी आरोप प्रमाणित होता है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के तहत नियम 18 के प्रावधानों के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्रीमती अलका सिन्हा से अभ्यावेदन प्राप्त

किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्रीमती अलका सिन्हा ने यह उल्लेख किया है कि (I) अधिनियम की सुसगत धारा के उचित पालन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम की सेवा संहिता के अनुसार दिशा-निदेश हेतु वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार किया। (II) आरोप में यह वर्णित नहीं है कि उनके किन कोताहियों की वजह से क्या परेशानी पैदा हुई। (III) अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कुर्सी, टेबुल रखवाया गया, परन्तु विरोध होने पर उसे हटवा दिया गया।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था, जिसके समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

इनके अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि बैठक बुलाने में यदि कोई वैधानिक समस्या थी, तो उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/जिला पदाधिकारी, पटना से स्वयं मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए था जो इनके द्वारा नहीं किया गया, सूफ़ी महोत्सव के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया गया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बिना आपसी समन्वय स्थापित किये कार्य किया गया। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4 संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती अलका सिन्हा पर प्रमाणित आरोप के लिए सचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती अलका सिन्हा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मनेर प्रखंड, पटना सम्प्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, गुप्तवार्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय (मुख्यालय) सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत सचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/-

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापाक :- स्था०1/आ०2-24/2015

1950

पटना, दिनांक: 26-09-18

प्रतिलिपि :-

सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक-849 दिनांक-25.03.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अवर सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. सहायक निदेशक(स्थापना/आहरण एवं व्ययन) निदेशालय, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8. श्रीमती अलका सिन्हा, कनीय सांख्यिकी सहायक, गुप्तवार्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय, मुख्यालय सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।